



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102020-222451
CG-DL-E-15102020-222451

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3170]
No. 3170]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 13, 2020/आश्विन 21, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2020/ASVINA 21, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3582.—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 1167(अ.), दिनांक 18 मार्च, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या मंत्रालय के ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

रामनगर वन्यजीव अभयारण्य जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित जम्मू जिले में, जम्मू शहर तहसील के नागरिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जम्मू वन संभाग के रामनगर खंड के कम्पार्टमेंट 1 से 4 में शामिल है। रामनगर वन्यजीव अभयारण्य जम्मू शहर के उत्तरी सीमांत पर स्थित वन के एक छोटा हरित पैच है जिसे शहर के एकमात्र हरित फुफ्फुस के रूप में जाना जाता है। अभयारण्य को सरकारी आदेश सं.136 दिनांक 10 अप्रैल, 1990 को अधिसूचित किया गया था और यह वन्यजीव संरक्षण विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और इसका प्रबंधन जम्मू वन्यजीव प्रभाग के माध्यम से किया जाता है। अभयारण्य जम्मू वन प्रभाग के रामनगर श्रेणी के रामनगर खंड के कम्पार्टमेंट 1,2,3, और 4 में शामिल है और 12.75 वर्ग किलोमीटर (एस.आर.ओ के अनुसार 31.5 किलोमीटर) क्षेत्र में आच्छादित है। क्षेत्र में सीमांकित वन शामिल है और यह मोटे तौर पर कील/खूंटे के आकार का है। यह क्षेत्र बस्तियों से घिरा हुआ है और भारी जैविक दबाव का सामना करता है। यह वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र वनस्पति और जीवजंतु की विविधता के समृद्ध संग्रह का भंडार है;

और, हाल ही में वनस्पति अध्ययन के अनुसार रामनगर वन्यजीव अभयारण्य में पौधों की 195 से अधिक प्रजातियों का आश्रय है। जिसमें जड़ी-बूटी, झाड़ियां, बेलें और वृक्ष शामिल हैं। फाइटो विविधता के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि वन का यह छोटा पैच जम्मू के आसपास वन क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक विविध और समृद्ध है। वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र के इस पैच के जीवजंतु प्रजाति में से कुछ, जिसमें सामान्य भारतीय तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, बनैला सूअर, नीलगाय, साही, लाल जंगली पक्षी, मोर, पायथन, रसेल वाइपर, कोबरा उल्लू शामिल हैं, अस्तित्व और संरक्षण पाते हैं;

और, यह क्षेत्र के साथ मिश्रित झाड़ी वनों के साथ कभी-कभी चीड़ वृक्षों से आच्छादित रहता है। चैंपियन और सेठ द्वारा संशोधित वर्गीकरण के अनुसार अभयारण्य की वनस्पति प्रमुख समूह "उप-उष्णकटिबंधीय उत्तरी मिश्रित शुष्क पर्णपाती वनों" के अंतर्गत आती हैं। अभयारण्य में कई प्रकार के उप-उष्णकटिबंधीय चौड़े पत्तों वाले वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख *अकाकिया मोडेस्टा* है। अभयारण्य में मुख्य वनस्पति में फुल्लई (*अकैशिया मोडेस्टा*), बबूल (*अकैशिया निलोटीका*), खैर (*अकैशिया कैटेचु*), हलदीन (*अदीना कार्डिफोलिया*), बाएल (*ऐगले मार्मेलोस*), सिरिस (*अल्बिजिया लेबेक*), खनवाल (*बाउहीनिया पुरपुरिया*), सिल्क ट्रे (*बोम्बक्स केइबा*), शिशम (*डालबेर्गिया सिस्सू*), तून (*तून किलिअटा*), बेर (*जिजिफस मॉरिटियना*), आदि उपलब्ध है;

और, रामनगर वन्यजीव अभयारण्य में स्तनधारियों में नीलगाय (*बोसेलाफुस ट्रागलोकामेलुस*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), रहेसुस बंदर (*मकाका मुलाट्रा*), सियार (*कैनिस् ऑरियस*), खरगोश (*लेपुस निगरिकोल्लिस*), साही (*हायस्ट्रीक इंडिका*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ्रा*), नेवला (*पेस्टेस एडवर्डसी*), आदि पाए जाते हैं। जबकि संरक्षित क्षेत्र से पक्षी-जीव सफेद बैक्रेड और बंगाल गिद्ध (*जिप्स बेंगालेंसिस*), शिकरा (*अक्लिपिटेर बाडिउस*), ब्लू रॉक फाख्ता (*कोलुम्बा लिविया*), कोयल (*इंडयनामयउस स्कलोपाकेया*), ग्रीन बारबेट (*भागलाइमा जेयलानिका*), हाउस स्विफ्ट (*अपस अफ्फिनस*), छोटा ग्रीन बी-ईटर (*मेरोपस ओरिइंटेलिस*), सामान्य वूड श्राइक (*टेफरोडोरिनिस पोंडीकेरिअनुस*), वाइट चेकड बुलबुल (*पयनोनोटस लेउकोगेनयस*), टिक्रेल फ्रोवर पेक्केर (*डीकेउम एरीथ्रोरेन्ट्रा*), पाइड बुश चैट (*सैक्सिकोला कैपरैटा*), वाइट आई (*जोस्टेरोपस पाल्पेरबरोसा*), आदि अभिलिखित किए गए हैं। संरक्षित क्षेत्र से सरीसृप जैसे रसेल्स पृथ्वी बोआ (*एरिक्स कोनिकस*), जॉन्स पृथ्वी बोआ (*इरयक्स जोहनि*), भारतीय चीता (*पायथन मोलुरस मोलुरस*), बिल्ली सांप (*बोइगा ट्रिगोनाटा*), सामान्य भारतीय क्रेट (*बुंगारुस केइरूलेउस*), रसेल वाइपर (*विपेरा रूसेल्ली*), आदि, जबकि तितलियों की प्रजाति जैसे पैपिलियो डिमोलस डिमोलस, पैपिलियो पोलयटेस रोमुलोउस, पार्नास्सिउस डेलिफउस अलर्किंसोनी, डानाउस लिमिअके लेओपरडुस, पेइरिस ब्रासिकय, कटोप्सिलिया पयरांथे पयरांथे,

मायकालेसिस मिनेउस मिनेउस, वाय्थिस्मा केयलोनिका हुइबनेकि, फलांटा फलांटा, इयथालिया अकोथेया, आदि अभिलिखित की गई है;

और, जम्मू शहर के विस्तार और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए, इस वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र के आसपास के शेष अवशिष्ट वन पैचों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही हितधारकों के हितों और घनी जनसंख्या वाले जम्मू शहर के प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग पर भी विचार किया जाना चाहिए। सरकार की वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के चारों तरफ झटके सहन करने वाला सुरक्षा कवच बनाने की सरकार की नीति है जिससे जंगली पशुओं को भोजन, आश्रय, प्रसव और जैवविविधताओं हेतु आवागमन सुनिश्चित करने के लिए गलियारे मिल सकें। सुप्रीम कोर्ट के निदेशों ने इसे और दृढ़ता दी है;

और, रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के समूहों का तथा उनके प्रचालन एवं प्रसंस्करण को निषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र शासित और जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला के रामनगर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) किलोमीटर से 1.850 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, नामतः :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार रामनगर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) किलोमीटर से 1.850 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 10.73 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी तरफ पारिस्थितिकी संवेदी जोन पीड़ियों से विद्यमान जम्मू शहर नगरपालिका की वजह से शून्य सीमा तक है।
- (2) रामनगर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपबंध-I** के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपबंध-II क, उपबंध-IIख, उपबंध-IIग और उपबंध-IIघ** के रूप में संलग्न है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और रामनगर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।
- (5) रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम एवं नगर क्षेत्र नहीं आते हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-
 - (i) पर्यावरण और वन;
 - (ii) कृषि;
 - (iii) राजस्व;
 - (iv) शहरी विकास;
 - (v) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - (vi) केंद्र शासित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
 - (vii) आवास और शहरी विकास;
 - (viii) ग्रामीण विकास;
 - (ix) सार्वजनिक निर्माण और विद्युत विकास;
 - (x) आपदा प्रबंधन;
 - (xi) नगर निगम पुंछ;
 - (xii) शहरी योजना विभाग पुंछ; और
 - (xiii) पंचायती राज।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-विभाजन के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में निषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें

स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- केंद्र शासित प्रदेश सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के क्षेत्र के रूप में प्रयोग या परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मॉनीटरिंग समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा-लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मॉनीटरिंग समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधार किया जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा-उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलस्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा दिशानिर्देश इस रीति से बनाए जाएंगे कि ऐसे क्षेत्रों विकास क्रियाकलापों को निषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और निर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा-यथा-संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा- संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा-संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;
- (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
क. निषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध होंगी। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडावर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित की जाएंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016, में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	निषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	निषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में	निषिद्ध।

	अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	निषिद्ध।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-विछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केवल विछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियमों और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

	जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	
17.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	फर्मी, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/वहिस्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/वहिस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/वहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	पारिस्थितिकी पर्यटना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	अवक्रमित भूमि/वनो/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति:- प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र. सं.	मानिटरि समिति का गठन	पद
(i)	जम्मू और कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	सदस्य सचिव जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(iii)	पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि (केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया जाना है)।	सदस्य;
(iv)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विषय विशेषज्ञ (जम्मू विश्वविद्यालय से केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	सदस्य;
(v)	प्रमुख सचिव, पर्यावरण और वन जम्मू और कश्मीर सरकार	सदस्य;
(vi)	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार	सदस्य;
(vii)	प्रमुख सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार	सदस्य;
(viii)	जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषि उत्पादन विभाग के प्रधान सचिव	सदस्य;
(ix)	प्रमुख सचिव, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार	सदस्य;
(x)	उपायुक्त से संबंधित	सदस्य;
(xi)	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य;
(xii)	सहायक वन्यजीव वार्डन संबंधित	सदस्य;
(xiii)	जम्मू और कश्मीर की मुख्य वन्यजीव वार्डन सरकार	सदस्य - सचिव

6. विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित

निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा. सं. 25/184/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपबंध -I

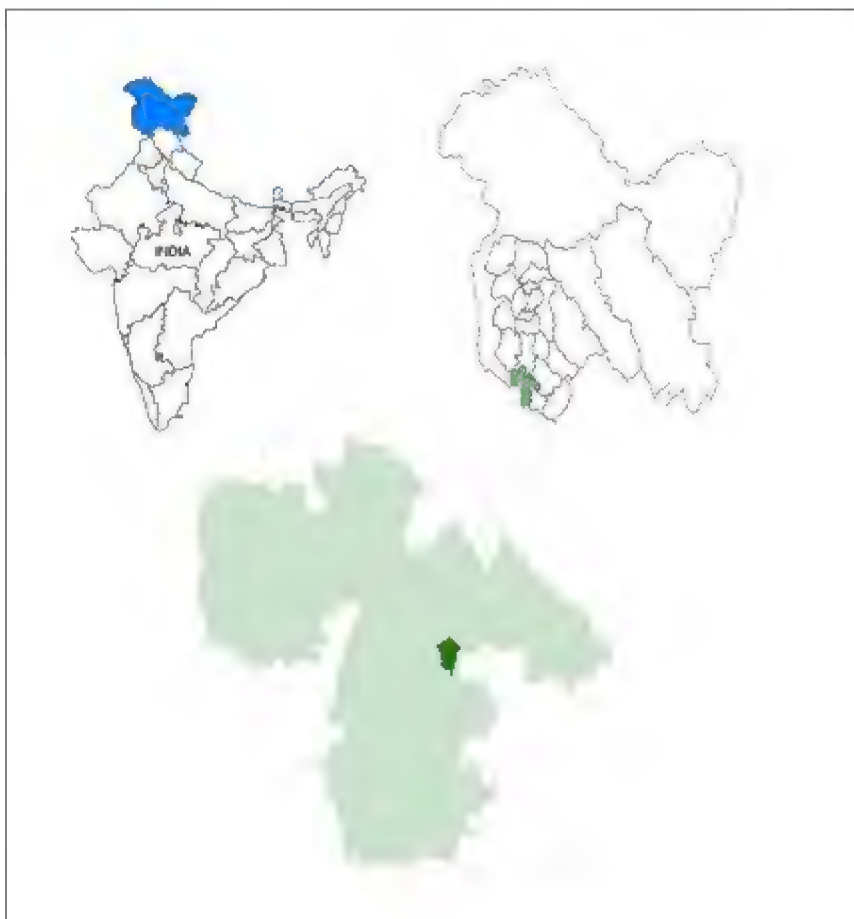
केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर में रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

क्र.सं.	अभयारण्य के संबंध में सीमाओं की दिशा	बिंदु	भू-निर्देशांक		टिप्पणी
			अक्षांश	देशांतर	
1	उत्तर	ए1	उ 32° 48' 11.67"	पू 74° 51' 32.70"	थाथेर ग्राम के चारों ओर का क्षेत्र
		बी1	उ 32° 47' 31.15"	पू 74° 52' 5.77"	
2	उत्तर पूर्व	सी1	उ 32° 47' 1.98"	पू 74° 52' 56.89"	खानपुर जेडीए कालोनी एवं पर्यावास के चारों ओर का क्षेत्र
		डी1	उ 32° 46' 17.93"	पू 74° 53' 42.28"	
3	पूर्व	ई1	उ 32° 46' 10.35"	पू 74° 53' 38.43"	तवी नदी एवं सिधरा ग्राम
		एफ1	उ 32° 45' 44.30"	पू 74° 53' 33.91"	
4	दक्षिण पूर्व	जी1	उ 32° 44' 56.49"	पू 74° 53' 22.24"	तवी नदी एवं जम्मू शहर नगर पालिका क्षेत्र बहुत पहले से विकसित है।
		एच1	उ 32° 44' 13.64"	पू 74° 53' 23.97"	

5	दक्षिण	आई1	उ 32° 45' 00.22"	पू 74° 52' 16.13"	जम्मू शहर पालिका क्षेत्र बहुत पहले से विकसित है।
		जे1	उ 32° 44' 50.42"	पू 74° 51' 47.08"	
6	दक्षिण पश्चिम	के1	उ 32° 45' 20.06"	पू 74° 51' 13.26"	जम्मू शहर पालिका क्षेत्र बहुत पहले से विकसित है।
		एल1	उ 32° 45' 48.74"	पू 74° 51' 10.85"	
7	पश्चिम	एम1	उ 32° 46' 19.70"	पू 74° 51' 04.73"	जम्मू शहर पालिका क्षेत्र बहुत पहले से विकसित है।
		एन1	उ 32° 48' 41.94"	पू 74° 51' 16.41"	
8	उत्तर पश्चिम	ओ1	उ 32° 46' 45.79"	पू 74° 50' 42.80"	जम्मू शहर पालिका क्षेत्र एवं केरन बस्ती बहुत पहले से विकसित है।
		पी1	उ 32° 47' 56.10"	पू 74° 50' 55.93"	

उपबन्ध - IIक

रामनगर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र



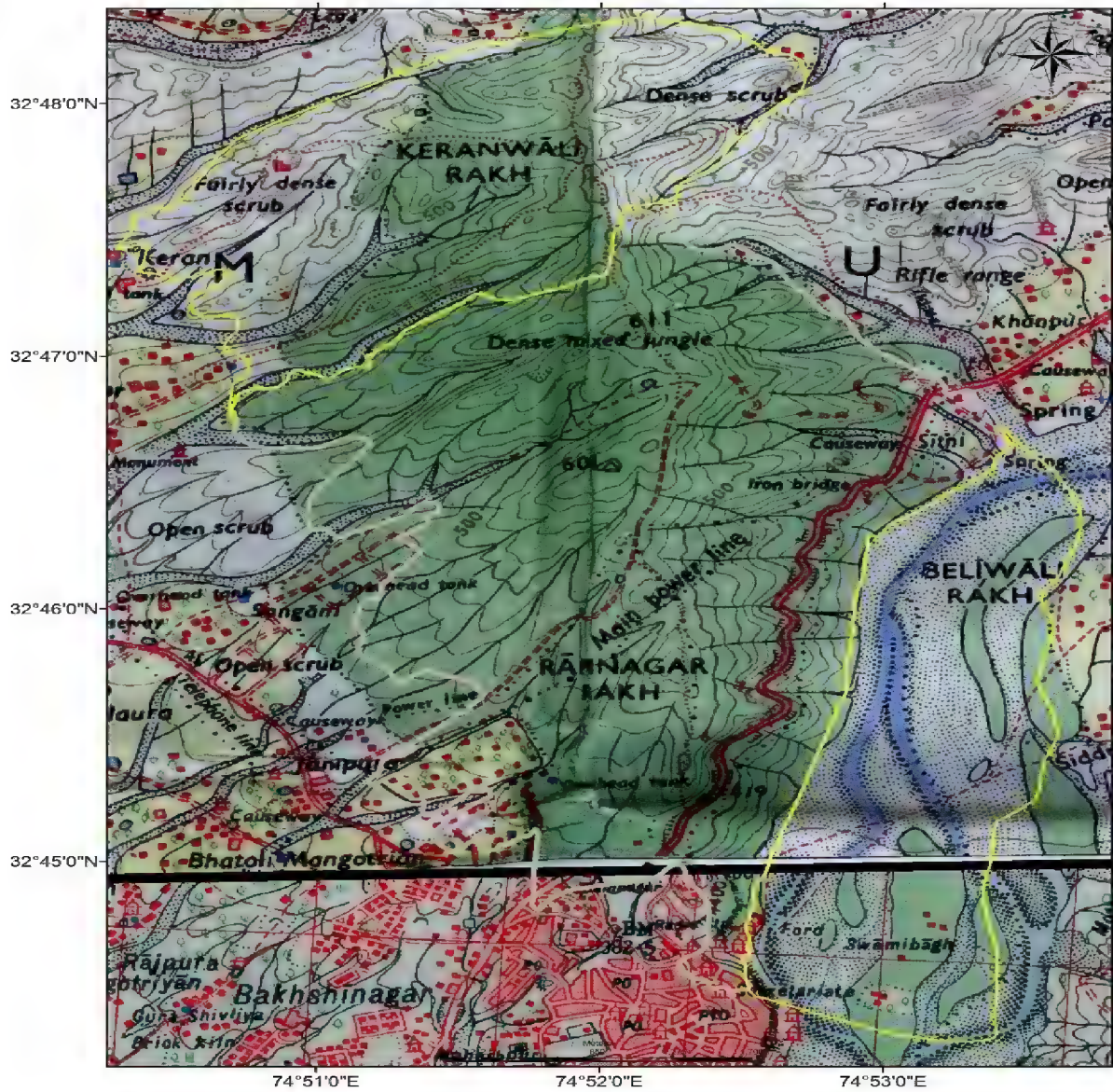
उपबंध -IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



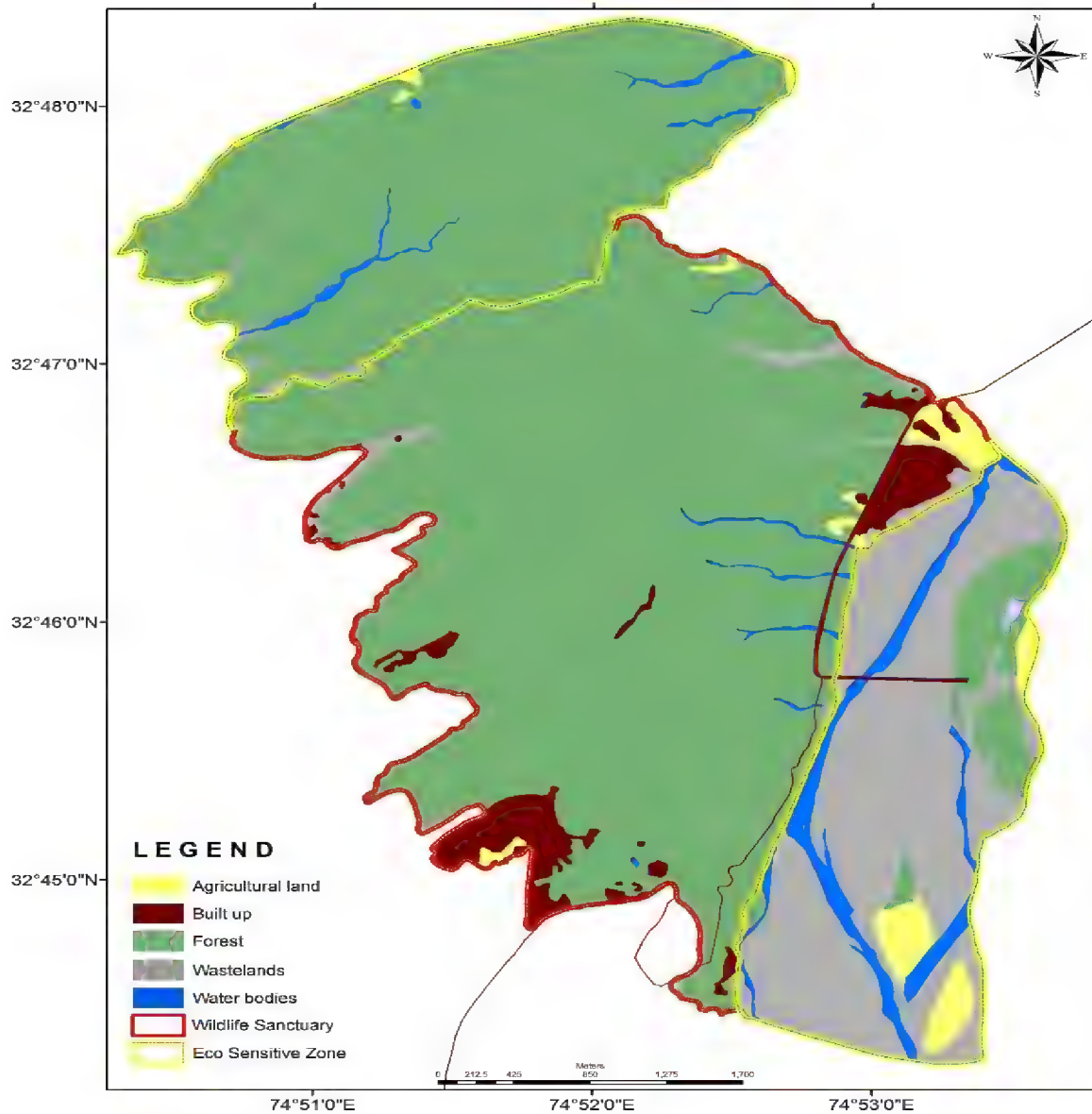
उपबंध - II ग

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का स्थलाकृतिक मानचित्र



उपबंध - IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र



उपबंध -III

सारणी क : रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	पहचान मुख्य बिंदु	मुख्य बिंदु के अवस्थान / दिशा	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	ए	उत्तर	उ 32° 47' 18.37"	पू 74° 51' 57.16"
	बी		उ 32° 47' 31.15"	पू 74° 52' 5.77"
2	सी	उत्तर पूर्व	उ 32° 47' 1.98"	पू 74° 52' 56.89"
	डी		उ 32° 46' 38.87"	पू 74° 53' 25.04"
3	ई	पूर्व	उ 32° 46' 16.36"	पू 74° 52' 58.36"
	एफ		उ 32° 45' 42.62"	पू 74° 52' 50.98"
4	जी	दक्षिण पूर्व	उ 32° 44' 52.03"	पू 74° 52' 31.55"
	एच		उ 32° 44' 37.02"	पू 74° 52' 29.65"
5	आई	दक्षिण	उ 32° 45' 00.22"	पू 74° 52' 16.13"
	जे		उ 32° 44' 50.42"	पू 74° 51' 47.08"
6	के	दक्षिण पश्चिम	उ 32° 45' 20.06"	पू 74° 51' 13.26"
	एल		उ 32° 45' 48.74"	पू 74° 51' 10.85"
7	एम	पश्चिम	उ 32° 46' 19.70"	पू 74° 51' 04.73"
	एन		उ 32° 48' 41.94"	पू 74° 51' 16.41"
8	ओ	उत्तर पश्चिम	उ 32° 46' 45.79"	पू 74° 50' 42.80"
	पी		उ 32° 47' 08.93"	पू 74° 51' 30.01"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	पहचान मुख्य बिंदु	मुख्य बिंदु के अवस्थान / दिशा	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	ए1	उत्तर	उ 32° 48' 11.67"	पू 74° 51' 32.70"
	बी1		उ 32° 47' 31.15"	पू 74° 52' 5.77"
2	सी1	उत्तर पूर्व	उ 32° 47' 1.98"	पू 74° 52' 56.89"
	डी1		उ 32° 46' 17.93"	पू 74° 53' 42.28"
3	ई1	पूर्व	उ 32° 46' 10.35"	पू 74° 53' 38.43"
	एफ1		उ 32° 45' 44.30"	पू 74° 53' 33.91"
4	जी1	दक्षिण पूर्व	उ 32° 44' 56.49"	पू 74° 53' 22.24"
	एच1		उ 32° 44' 13.64"	पू 74° 53' 23.97"
5	आई1	दक्षिण	उ 32° 45' 00.22"	पू 74° 52' 16.13"
	जे1		उ 32° 44' 50.42"	पू 74° 51' 47.08"

6	के1	दक्षिण पश्चिम	उ 32° 45' 20.06"	पू 74° 51' 13.26"
	एल1		उ 32° 45' 48.74"	पू 74° 51' 10.85"
7	एल1	पश्चिम	उ 32° 46' 19.70"	पू 74° 51' 04.73"
	एन 1		उ 32° 48' 41.94"	पू 74° 51' 16.41"
8	ओ 1	उत्तर पश्चिम	उ 32° 46' 45.79"	पू 74° 50' 42.80"
	पी1		उ 32° 47' 56.10"	पू 74° 50' 55.93"

उपबंध -IV**की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th October, 2020

S.O. 3582 (E).— In supersession of Ministry's draft notification S.O. 1167(E), dated 18th March, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Ramnagar Wildlife Sanctuary falls within the civil jurisdiction of Jammu City Tehsil, District Jammu in the Union territory of Jammu and Kashmir and comprises of compartments 1 to 4 of the Ramnagar block of Jammu Forest Division. Ramnagar Wildlife Sanctuary located on the northern fringe of Jammu city is a small green

patch of forest which is valued as the only green lung of the city. The Sanctuary was notified *vide* Govt. Order No.136 dated 10th April, 1990 and is under the administrative control of Department of Wildlife Protection, Jammu and Kashmir Government and is managed through Wildlife Division Jammu. The Sanctuary comprising of compartments 1,2,3 and 4 of Ramnagar Block of Ramnagar Range of Jammu Forest Division and covers an area of 12.75 square kilometers (31.5 square kilometers as per the S.R.O). The area comprises of demarcated forest and is roughly wedge shaped. The area is surrounded by habitations and faces heavy biotic pressure. This wildlife protected area is repository of rich assemblage of floral and faunal diversity;

AND WHEREAS, according to a recent floral study the Ramnagar Wildlife Sanctuary houses more than 195 species of plants including herbs, shrubs, climbs and tree. A comparative study of phyto diversity shows that this small patch of forest is much more diverse and rich than surrounding forest areas of Jammu. The faunal species, some of which include common Indian leopard, barking deer, wild boar, nilgai, porcupine, red jungle fowl, peafowl, python, russell viper, cobra owe their existence and protection to this patch of wildlife protected area;

AND WHEREAS, the area is covered with mixed scrub forests with occasional chir trees. The vegetation of the Sanctuary as per the revised classification by Champion and Seth comes under the major group "Sub-tropical Northern Mixed Dry Deciduous Forests." A variety of sub-tropical broad leaved trees and shrubs are found in the Sanctuary, the dominant among them being *Acacia modesta*. The main flora available in the Sanctuary are phullai (*Acacia modesta*), babul (*Acacia nilotica*), Khair (*Acacia catechu*), haldin (*Adina cardifolia*), bael (*Aegle marmelos*), siris (*Albizia lebbek*), khanwal (*Bauhinia purpurea*), silk cotton tree (*Bombax ceiba*), shisham (*Dalbergia sissoo*), toon (*Toona ciliata*), ber (*Ziziphus mauritiana*), etc;

AND WHEREAS, the mammal found in the Ramnagar Wildlife Sanctuary are nilgai (*Boselaphus traglocamelus*) spotted deer (*Axis axis*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), rhesus monkey (*Macaca mulatta*), jackal (*Canis aureus*), hare (*Lepus nigricollis*), porcupine (*Hystrix indica*), wild boar (*Sus scrofa*), mongoose (*Herpestes edwardsii*), etc. While avifauna recorded from the protected area are white backed or Bengal vulture (*Gyps bengalensis*), shikra (*Accipiter badius*), blue rock dove (*Columba livia*), koel (*Endynamyus scolopacea*), green barbet (*Magalaima zeylanica*), house swift (*Apus affinis*), small green bee-eater (*Merops orientalis*), common wood shrike (*Tephrodorinis pondicerianus*), white checked bulbul (*Pycnonotus leucogenys*), Tickell's frower pecker (*Diceum erythrorhyncha*), pied bush chat (*Saxicola caprata*) white eye (*Zosterops palperbroza*), etc. Reptiles such as Russell's earth boa (*Eryx conicus*), John's earth boa (*Eryx johnii*), Indian python (*Python molurus molurus*), cat snake (*Boiga trigonata*), common Indian krait (*Bungarus caeruleus*), russell viper (*Vipera russelli*), etc. while butterflies species such as *Papilio demoleus demoleus*, *Papilio polytes romulous*, *Parnassius delphius alkinsoni*, *Danaus limiace leopardus*, *Pieris brassicae*, *Catopsilia pyranthe pyranthe*, *Mycalesis mineus mineus*, *Ypthisma ceylonica huebneci*, *Phalanta phalantha phalantha*, *Euthalia aconthea*, etc. are recorded from the protected area;

AND WHEREAS, keeping in view the expansion of Jammu city and increasing pressure on the natural resources the threat looming large over the remaining residual forest patches around this wildlife protected area is understandable. At the same time considering the interests of stake holders and thickly populated Jammu town sustainable use of natural resources has to be given due consideration. The policy of the government to have shock-absorbing protective covers around Wildlife Protected Areas providing corridors to ensure dispersal and movement of wild animals for food, shelter, procreation and safeguard of biodiversity has been further strengthened by the Supreme Court's directions;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Ramnagar Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1.850 kilometres around the boundary of Ramnagar Wildlife Sanctuary, in Jammu district in the Union territory of Jammu and Kashmir as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) kilometre to 1.850 kilometres around the boundary of Ramnagar Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 10.73 square kilometres. *Zero extent of Eco-sensitive Zone towards south, south-west and west side are due to the existing Jammu city municipal area prevailing since generations.*

(2) The boundary description of Ramnagar Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

- (3) The maps of the Ramnagar Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC and Annexure-IID.**
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Ramnagar Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure III.**
 - (5) There is no village or township falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Ramnagar Wildlife Sanctuary.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**—(1) The Union territory Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of Union territory.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan: -
 - (i) Environment and Forest;
 - (ii) Agriculture;
 - (iii) Revenue;
 - (iv) Tourism;
 - (v) Irrigation and Flood Control;
 - (vi) Union territory Pollution Control Board.
 - (vii) Housing and Urban Development;
 - (viii) Rural Development;
 - (ix) Public Works and Power Development;
 - (x) Disaster Management;
 - (xi) Municipal Corporation Poonch;
 - (xii) Department of Town Planning Poonch; and
 - (xiii) Panchayati Raj.
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
 - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
 - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
 - (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the Union territory Government.- The Union territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union territory Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union territory Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**— (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Union territory Department of Tourism in consultation with Union territory Departments of Environment and Forests.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
 - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
 - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger

Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by Union territory Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the

Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the Union territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

- (15) **Vehicular pollution.**— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**— The protection of hill slopes shall be as under:—
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.— All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer,

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the Union territory Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or Union territory Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	area.	made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Open Well, Bore Well etc for agriculture or other usage.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

- 5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Chief Secretary to the Government of Jammu & Kashmir	Chairman, ex officio
(ii)	Member Secretary Jammu & Kashmir Union territory Pollution Control Board	Member;
(iii)	One representative of Non-Government organization working in the field of Environment (to be nominated by the Union territory Govt.)	Member;
(iv)	One subject expert in the field of ecology and environment (from Jammu University to be nominated by the Union territory govt.)	Member;
(v)	Principal Secretary, Environment and Forest Jammu & Kashmir Government	Member;
(vi)	Principal Secretary, Revenue Department Jammu & Kashmir Government	Member;
(vii)	Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department Jammu & Kashmir Government	Member;
(viii)	Principal Secretary, Agriculture Production Department of Jammu & Kashmir Government	Member;
(ix)	Principal Secretary, Irrigation & Flood Control Department Jammu & Kashmir Government	Member;
(x)	Deputy Commissioner concerned	Member;
(xi)	Divisional Forest Officer concerned	Member;
(xii)	Assistant Wildlife Warden concerned	Member;
(xiii)	Chief Wildlife Warden Government of Jammu & Kashmir	Member-Secretary.

- 6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the Union territory Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the Union territory Government.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union territory as per proforma appended at **Annexure IV**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and Union territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/184/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECOSENSITIVE ZONE AROUND RAMNAGAR WILDLIFE
SANCTUARY IN THE UNION TERRITORY JAMMU AND KASHMIR**

S. No	Direction w.r. t boundaries of the Sanctuary	Point	Geo-coordinates		Remarks
			Latitude	Longitude	
1	North	A1	N 32° 48' 11.67"	E 74° 51' 32.70"	Area surrounded by Thather village
		B1	N 32° 47' 31.15"	E 74° 52' 5.77"	
2	North East	C1	N 32° 47' 1.98"	E 74° 52' 56.89"	Area surrounded by Khanpur JDA colony & habitation.
		D1	N 32° 46' 17.93"	E 74° 53' 42.28"	
3	East	E1	N 32° 46' 10.35"	E 74° 53' 38.43"	River Tawi & Sidhra village.
		F1	N 32° 45' 44.30"	E 74° 53' 33.91"	
4	South East	G1	N 32° 44' 56.49"	E 74° 53' 22.24"	River Tawi & Jammu city municipal area already developed from generations.
		H1	N 32° 44' 13.64"	E 74° 53' 23.97"	
5	South	I1	N 32° 45' 00.22"	E 74° 52' 16.13"	Jammu city municipal area already developed from generations.
		J1	N 32° 44' 50.42"	E 74° 51' 47.08"	

6	South West	K1	N 32° 45' 20.06''	E 74° 51' 13.26''	--do--
		L1	N 32° 45' 48.74''	E 74° 51' 10.85''	
7	West	M1	N 32° 46' 19.70''	E 74° 51' 04.73''	--do--
		N1	N 32° 48' 41.94''	E 74° 51' 16.41''	
8	North West	O1	N 32° 46' 45.79''	E 74° 50' 42.80''	Jammu city municipal area already developed from generations & Keran habitation.
		P1	N 32° 47' 56.10''	E 74° 50' 55.93''	

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF RAMNAGAR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE



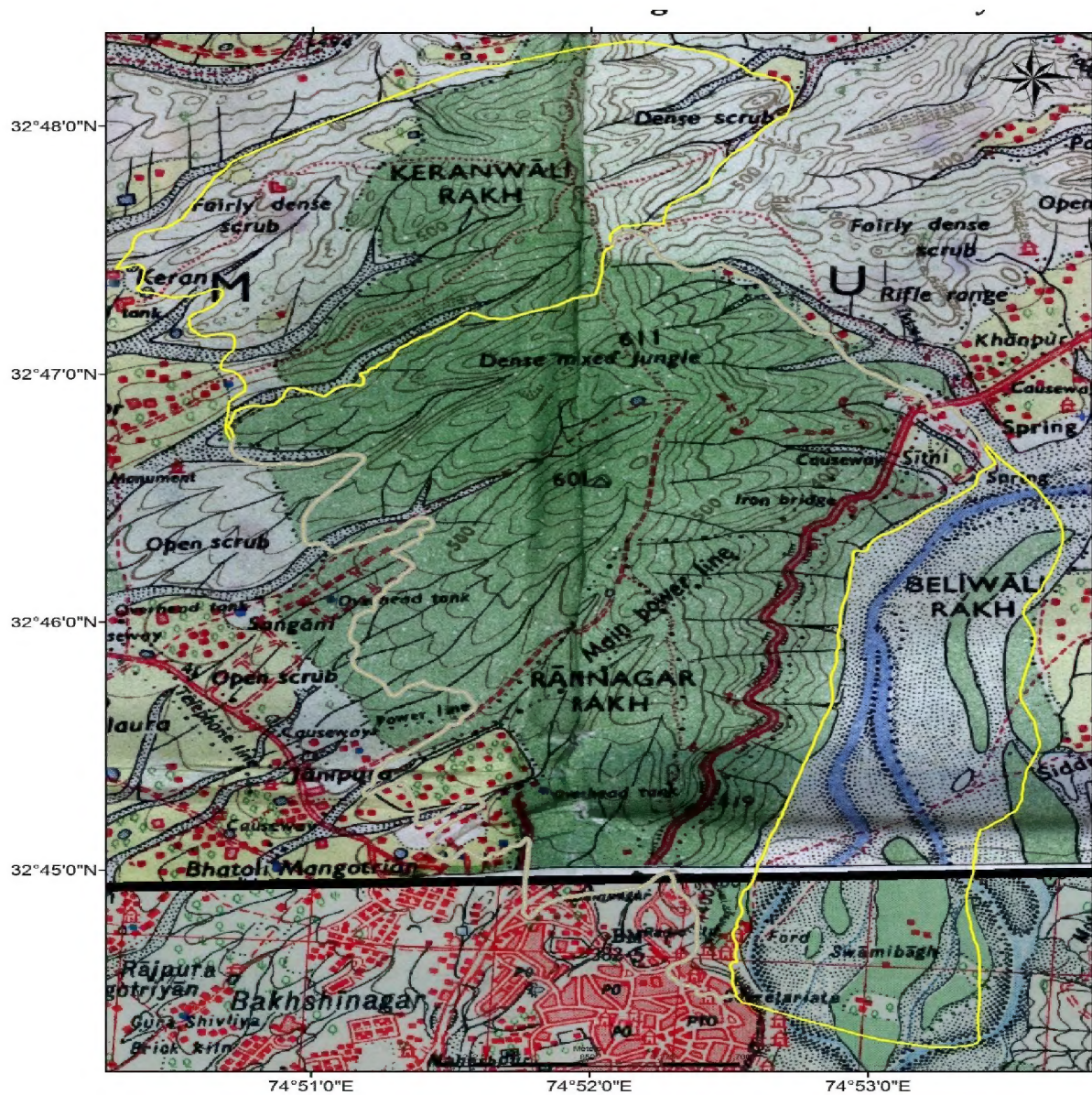
ANNEXURE- IIB

**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMNAGAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



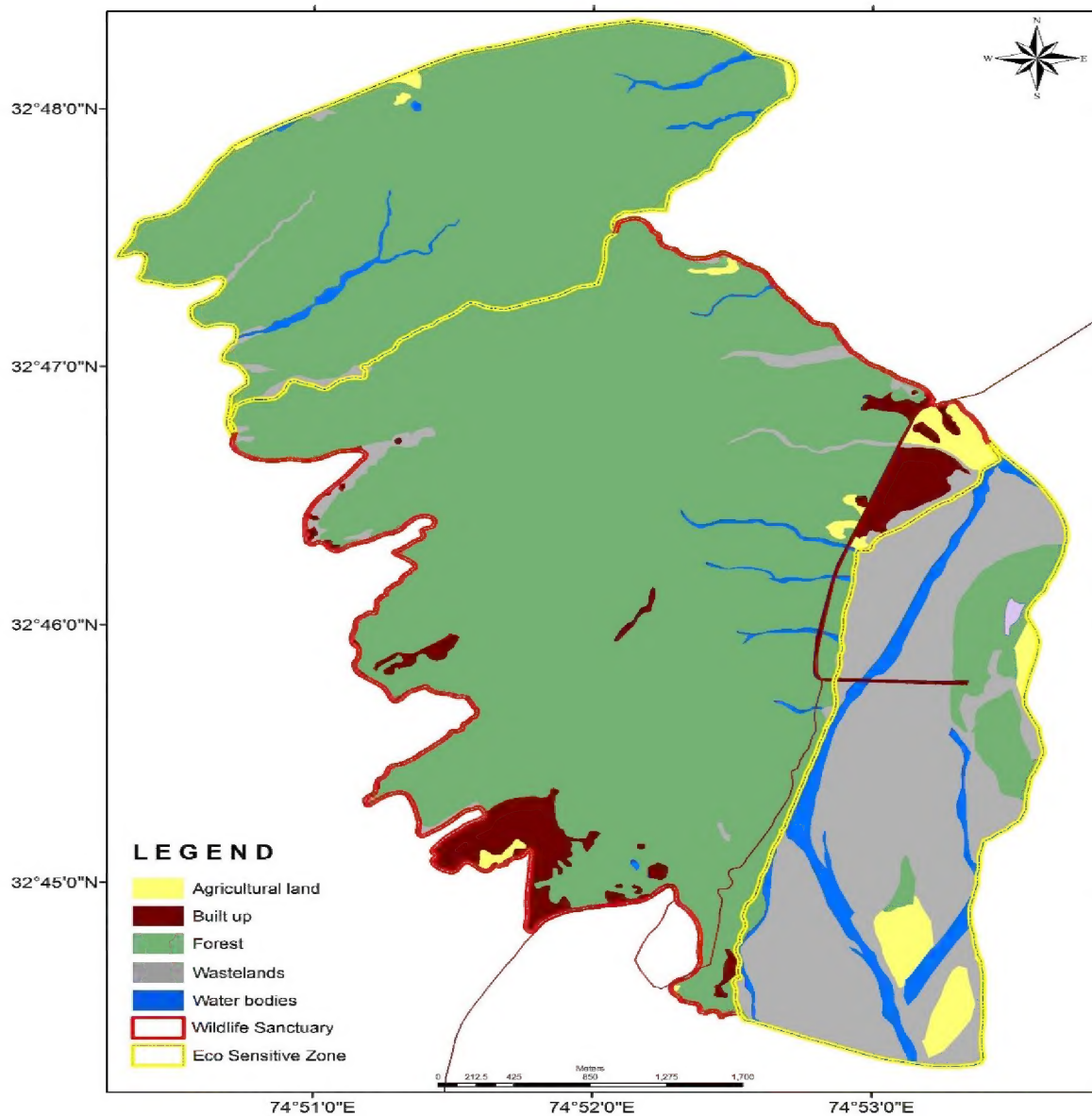
ANNEXURE- IIC

**TOPOGRAPHIC MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMNAGAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG
WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI)
TOPOSHEET**



ANNEXURE- IID

**MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMNAGAR WILDLIFE
SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF RAMNAGAR WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Identification Prominent Points	Location / Direction of Prominent point	Geo-Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	A	North	N 32° 47' 18.37''	E 74° 51' 57.16''
	B		N 32° 47' 31.15''	E 74° 52' 5.77''
2	C	North East	N 32° 47' 1.98''	E 74° 52' 56.89''
	D		N 32° 46' 38.87''	E 74° 53' 25.04''
3	E	East	N 32° 46' 16.36''	E 74° 52' 58.36''
	F		N 32° 45' 42.62''	E 74° 52' 50.98''
4	G	South East	N 32° 44' 52.03''	E 74° 52' 31.55''
	H		N 32° 44' 37.02''	E 74° 52' 29.65''
5	I	South	N 32° 45' 00.22''	E 74° 52' 16.13''
	J		N 32° 44' 50.42''	E 74° 51' 47.08''
6	K	South West	N 32° 45' 20.06''	E 74° 51' 13.26''
	L		N 32° 45' 48.74''	E 74° 51' 10.85''
7	M	West	N 32° 46' 19.70''	E 74° 51' 04.73''
	N		N 32° 48' 41.94''	E 74° 51' 16.41''
8	O	North West	N 32° 46' 45.79''	E 74° 50' 42.80''
	P		N 32° 47' 08.93''	E 74° 51' 30.01''

ANNEXURE-III

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Identification Prominent Points	Location / Direction of Prominent point	Geo-Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	A1	North	N 32° 48' 11.67''	E 74° 51' 32.70''
	B1		N 32° 47' 31.15''	E 74° 52' 5.77''
2	C1	North East	N 32° 47' 1.98''	E 74° 52' 56.89''
	D1		N 32° 46' 17.93''	E 74° 53' 42.28''
3	E1	East	N 32° 46' 10.35''	E 74° 53' 38.43''
	F1		N 32° 45' 44.30	E 74° 53' 33.91''
4	G1	South East	N 32° 44' 56.49''	E 74° 53' 22.24''
	H1		N 32° 44' 13.64''	E 74° 53' 23.97''
5	I1	South	N 32° 45' 00.22''	E 74° 52' 16.13''
	J1		N 32° 44' 50.42''	E 74° 51' 47.08''
6	K1	South West	N 32° 45' 20.06''	E 74° 51' 13.26''
	L1		N 32° 45' 48.74''	E 74° 51' 10.85''
7	M1	West	N 32° 46' 19.70''	E 74° 51' 04.73''
	N1		N 32° 48' 41.94''	E 74° 51' 16.41''
8	O1	North West	N 32° 46' 45.79''	E 74° 50' 42.80''
	P1		N 32° 47' 56.10''	E 74° 50' 55.93''

ANNEXURE –IV**Performa of Action Taken Report:-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.